कृषि क्षेत्र के विकास मे नाबार्ड की भूमिका (भोपाल संभाग के विशेष संदर्भ में)

रजनीश तिवारी[1], डॉ. बासंती मैथ्यू मर्लिन[2], डॉ. विजय सिंह[3]
[1]शोधार्थी, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
[2]विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
[3]कुलसचिव, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास का प्रमुख स्थान है, भारत की लगभग 65 से 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपना जीवन कृषि व उसके उत्पन्न उत्पाद व उससे जुड़े उद्योग से ही चलाते है। यदि तुलना की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रो व शहरी क्षेत्रो के जीवन यापन मे काफी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रो मे सुविधाओं का अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रो से सरकारी सेवाएँ, अस्पताल, स्कूल व अन्य आवश्यक सेवाओं का अभाव व दूरी दिखाई देती है। आज के समय ग्रामीण विकास एक राष्ट्रीय आवश्क्ता है भारत व उसके विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरह है। ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण लोगों के आर्थिक व सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाना परम आवश्यक है। इसी कारण भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापनार 12 जुलाई 1982 मे की गई। जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को पुनवित्त सहायता प्रदान कर ग्रामीण विकास को बढ़ाना व गरीबी को कम करना है। जिसमे ऋण और अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भारत सरकार की विकास नीतियों के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण स्कीम को सफल बनाना मुख्य उद्देश्य है। यह एक एकीकृत संगठन है, इसका कार्य ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक ऋण की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को समझना है। अतः इस शोध पत्र के माध्यम से ग्रामीण व कृषि विकास में नाबार्ड की भूमिका का अध्ययन किया गया है। जिसमे संबंधित उद्देश्यों के साथ ही संबंधित विभिन्न गतिविधियों व क्रियाओं का अध्ययन शामिल है। नाबार्ड प्रबंधन उनके संगठन निर्माण, धन के श्रोत, बैंको की भूमिका, संस्थानों को ऋण सहायता, माइक्रों वित्त गतिविधी आदि प्रमुख बिंदुओ पर कार्य किया गया है जिसका माध्यम सहायक समंक है जिसमे विभिन्न रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, नाबार्ड रिपोर्ट आदि के श्रोत का प्रयोग किया गया है।

प्रमुख बिंदू: नाबार्ड, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म वित,।

I परिचय

भारत की जनसंख्या का लगभग 65 से 70 प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करती है। जिसमे कृषक, मजदूर विभिन्न जनजातियों आदि सभी का निवास है। परंतु विकास का स्तर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों मे पिछड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों मे अभी भी शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, यातायात के साधनों में कमी आदि विभिन्न प्रकार की बुनियादी समस्याओं का अभाव है। इसका मुख्य कारण वह युवा वर्ग भी है जो की तरक्की के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर शहरी क्षेत्रो की तरफ जा रहे है। सरकार का प्रयास इस क्षेत्र को मजबूत बनाना है साथ ही शिक्षत वर्ग से उम्मीदे है की वह ग्रामीण क्षेत्रो के विकास मे अपनी शिक्षा का सही उपयोग कर अपना योगदान दे इसी प्रकार सरकार का लक्ष्य ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को सफल बनाना भी है।

कई समय पहले ग्रामीण क्षेत्रों मे ऋण प्राप्ति के विभिन्न साधनों के अभाव के कारण साहूकारो पर निर्भर रहना पड़ता था जिसका मुख्य कारण विकास दर धीमे होना, शिक्षा का अभाव, जन–जन जागरूकता का अभाव व सुविधिाओं की कमी थी। जिसके कारण ग्रामीणजन अपनी अज्ञानता, अशिक्षा के कारण साहूकारों से ऋण लेकर ऊँची ब्याज दर व वसूली के कारण अपने जीवन मे परेशानी महसूस करते थे। जिसका परिणाम कृषकों पर ऋण का बोझ बढ़ना व उसे अपनी खेती को गवा देना व मजदूरी करना आदि समस्याओं से ग्रसित होना पड़ता था। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए व साहूकारी प्रथा को समाप्त करने के लिए वित्त सहायता एजेंसियां, सहकारी ऋण समितियों का गठन किया गया। इस समय वाणिज्यिक बैंको ने अपना सीधा योगदान वित्त प्रदान करने मे नहीं दिया था । राष्ट्रीयकरण के बाद, कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए ऋण देने का निर्देश किया गया है। लेकिन यह देखा गया कि छोटे किसान, खेतीहर मजदूर आदि इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के समाज के कमजोर वर्गो जिनको आर्थिक सहायता की आवश्क्ता होती है जिसके लिए रिजर्व बैंक व वाणिज्यिक बैंक उनकी ऋण संबंधी जरूरतो को पूरा करने के लिए असमर्थ दिख रही थी इस कारण यह प्रक्रिया यह पूरी तरह विफल रही। भारत सरकार के द्वारा एक नई शुरूआत की गई जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 मे की गई। जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को पुनवित्त सहायता प्रदान कर ग्रामीण विकास को बढ़ाना व गरीबी को कम करना है। जिसमे ऋण और अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भारत सरकार की विकास नीतियों के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण स्कीम को सफल बनाना मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीणी कृषि व उससे जुड़े उद्योग जैसे कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प आदि विभिन्न गतिविधिओं का प्रोत्साहन देना नाबार्ड का मुख्य कार्य है। नाबार्ड पुनवित्त मे वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंको ने पुमुख योगदान दिया है।

II अध्ययन की आवश्कता तथा उद्देश्य

(क) अध्ययन की आवश्कता – अध्ययन का कारण भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था व उसके महत्व को समझना है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मे प्रमुख योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है। भारत की लगभग 65 से 70 प्रतिशत

आबादी ग्रामीण क्षेत्रो मे निवास करना इसका मुख्य कारण है। उनकी आजिविका व आय के श्रोतों की पहचान करना साथ ही आजिविका के श्रोतों को विकास की धारा मे जोड़ना भी मुख्य कार्य है। ग्रामीण सेवाओं का अध्ययन व उसमे कमी को समझते हुए कारणों की जांच करना व शहरी क्षेत्रो की सुविधाओं से तुलना करना भी इस अध्ययन का प्रमुख कारण है। ग्रामीण सेवाएं जिनमे स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, यातायात, पानी, सीवेज, सड़क, प्रकाश आदि का अभाव देखा गया है। इसी प्रकार आजादी के समय भारतीय ग्रामीण आबादी लगभग 83 प्रतिशत थी । आज यह लगभग 65 से 70 प्रतिशत है, शहरी विकास को आजादी के बाद से ही बढावा मिला है परंतु ग्रामीण विकास अभी भी पिछड़ा हुआ है। इसी कारण भारत सरकार द्वारा रणनीति के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई। जिसका मुख्य उददेश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण जन जीवन का विकास करना है। इस कार्य के साथ ही नाबार्ड की भूमिका का ग्रामीण विकास मे अध्ययन करना भी प्रमुख उददेश्य है।

(ख) उददेश्य :

(i) ग्रामीण विकास मे नाबार्ड की भूमिका का अध्ययन ।
(ii) नाबार्ड पुनवित्त का आकलन करना।
(iii) ऋण सहायता कार्यक्रम का अध्ययन।

(ग) स्मंक संग्रह और सांख्यिकीय तकनीको का अध्ययन :
नाबार्ड वार्षिक प्रतिवेदन, विभिन्न शोध पत्र, वेबसाईट व अन्य सहायक समंको का प्रयोग कर सांख्यिकीय गणनाओं को प्रयोग कर निष्कर्ष इस शोध पत्र मे प्रदान किया गया है।

(घ) अवधि का चयन अध्ययन प्रक्रिया में :
इस शोध पत्र का अधार वर्ष 2010–2011 से 2015–2016 तक के समंको को आधार बनाकर किया गया है।

(च) विस्तार :
विस्तार के रूप मे नाबार्ड की भूमिका का ग्रामीण उत्थान से आकलन करने का प्रयास किया गया है। जिसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर नाबार्ड व उसके कार्यो को ग्रामीण उत्थान से जोड़ कर देखा गया है। पुरवित्त सहायता जो कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों व वाणिज्यिक बैंकों आदि के माध्यम से की जा रही है। जो कि सूक्ष्म वित्त को परिभाषा को प्रदर्शित करती है।

III नाबार्ड का प्रोफाइल

देश के एकिकृत ग्रामीण विकास मे क्रेडिट एवं महत्वपूर्ण आवश्यक्ता के रूप मे देखा जा रहा है। इसी कारण नाबार्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। नशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एवं रूरल डवलपमेंट (नाबार्ड) ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत पूनवित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई हैं। देश मे नाबार्ड के कई कार्यालय है जिसके कई विभाग भी है। वर्तमान मे डॉ.जी.आर. चिंतला नाबार्ड के 2020 से अध्यक्ष है।

इससे पहले आरबीआई हमेशा से सक्रीय भूमिका मे रहा है परंतु समय के साथ आरबीआई का कार्य बढ़ता चला गया एवं इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर अलग से ध्यान दे पाना आरबीआई के लिए संभव नही था इसी कारण एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एवं डवलपमेंट कॉरपोरेशन (एआरडीसी) पुनवित्त की आवश्कताओं की पूति करने मे पूरी तरह सफल नही हो पाया। इसी कारण आरबीआई की भूमिका कृषि वित्त के क्षेत्र मे कम होती चली गई इसी कारण उस समय श्री सिरमारन के अधीन एक समिति का गठन किया गया है। जिसके बाद 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड को गठन किया गया।

(क) नाबार्ड की प्रमुख जिम्मेदारियॉ :

(i) नाबार्ड का कार्य कृषि क्षेत्र को पनवित्त प्रदान करना है।
(ii) नाबार्ड कृषि विकास नीति, योजना एवं उसके संचालन संबंधि मामलो से संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।
(iii) नाबार्ड उन संस्थाओं से भी संबंधित है जो कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पुनवित्त सुविधा प्रदान करती है।
(iv) नाबार्ड ग्रामीण विकास के उद्देश्यो से चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदारी उठाता है।
(v) नाबार्ड आरबीआई विनियमन और पर्यवेक्षण के तहत नाबार्ड की भूमिका अग्रणी है यह सहकारी बैंको, जिला सहकारी केंन्द्रीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की देखरेख करता है । इन बैंको के माध्यम से अपनी गतिविधियों को साकार करने का प्रयास भी करता है।

(ख) नाबार्ड के उद्देश्य :

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
(ii) ग्रामीण सुविधाओ के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना।
(iii) कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प कारीगरों और किसानों को वित्त सुविधि प्रदान करना।
(iv) ऋण संस्थाओं के पुनर्वास एवं बैंक कर्मियों के प्रशिक्षण द्वारा ऋण वितरण प्रणाली मे सुधार करना।
(v) विभिन्न एजेंसियों व ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियांवयन मे तालमेल स्थापित करना साथ ही गतिविधियों को मोनिटरिंग व मूल्यांकित करना भी इसके कार्यो मे शामिल है।
(vi) नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़वा देता है साथ ही विकास से लिए आवश्यक निधि को बनाए रखता है।

(ग) नाबार्ड संगठन संरचना:

(i) अध्यक्ष
(ii) प्रबंध निदेशक
(iii) दो निदेशक (ग्रामीण विकास एवं अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों मे से)
(iv) तीन निदेशक जो कि सहकारी बैंकिंग या वाणिज्यिक बैंकिंग मे अनुभव रखते हो।
(v) तीन अन्य निदेशक
(vi) दो अन्य निदेशक

(vii) दो अन्य राज्य सरकार की ओर से निदेशक आदि

अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है एवं उनके साथ के प्रबंध निदेशको का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

(घ) निधि के श्रोत का प्रकार :

(i) नाबार्ड का आरंभ कोष रूपये 100 करोड़ था

(ii) रिर्जर्व बैंक द्वारा रूपये 2,00,00 करोड़ का कोष प्रदान किया। भारत सरकार द्वारा भी 4,980 करोड़ रूपये का कोष प्रदान किया गया यह मार्च 2016 के समंको पर आधारित है।

(च) नाबार्ड की गतिविधियॉ:

नाबार्ड एक प्रकार का एकीकृत संगठन है जो कि, कृषि क्षेत्र व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। इससे संबंधत वर्ष 2011 से 2016 तक के आधार पर गतिविधियों का चित्रण इस प्रकार से है:

(छ) नाबार्ड निर्माण विकास सहायता (एनआईडीए) :

ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वित्तपोषण प्रदान किया गया है। एनआईडीए ने इसके लिए वित्तपोषण सुविधा को सरल व लचीला रूप प्रदान कर ऋण प्रादान किया, जिससे ग्रामीण इन्फ्रास्टक्चर का निर्माण हो सके।

(ज) वित्तपोषण और समर्थन निर्माता संगठन :

वर्ष 2011 की निधि के माध्यम से उत्पाद स्तर पर भी ऋण प्रणाली को लचीला बनाया गया है। जिससे उत्पाद संगठनों को समर्थन किया जा सके व उत्पाद क्षमता को बढ़ावा मिल सके ।

(झ) मध्यम अवधि के ऋण :

नाबार्ड द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए व प्राकृतिक आपदाओ से निपटने के लिए मध्यम अवधि के ऋण भी प्रदान किए जाते है जिसमे सहकारी बैंको की मुख्य भूमिका है।

(ट) लम्बी अवधी के लिए ऋण :

नाबार्ड द्वारा 3 से 15 वर्ष के अवधि के लिए भी कृषको को ऋण प्रदान किए जाते ीरहे है जिससे की वह सिंचाई, कृषि, मशीनीकरण, भूमि विकास, डेयरी, पशुपालन, वृक्षारोपण, बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन, भंडारण जैसे क्षेत्रों मे विकास कर अपनी आय को बढ़ा सके व अपने जीवन स्तर को सुधार सके।

(ठ) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियॉ :

पंजीकृत सहकारी समिति (पैक्स) अपने सदस्यों को ऋण सेवाएं प्रदान करता रहता है इसकी सदस्यता वाले ग्रामीण इनकी सहायता से अपनी गतिविधियों को गती प्रदान कर पाते है। कृषि–संग्रहण केंद्र, कृषि सेवा केन्द्र, कृषि प्रसंस्करण केंद्र, कृषि जानकारी जो की विपणन से भी संबंधित है इसका लाभ पीएसीएस द्वारा लिया जा सकता है।

(ड) डेयरी उद्यमिता विकास योजना :

वर्ष 2010 मे आधुनिक डेयरी फामों को प्रात्साहित किया जाता रहा है। अच्छे प्रजनन संरक्षण के लिए तकनीकी ज्ञान व स्वच्छ दूध और बछिया पालन का ध्यान व सही उत्पादन करना व सुधार तकनीको को बढ़वा देना भी शामिल है।

IV विभिन्न संस्थाओं को ऋण सहायता

नाबार्ड विभिन्न संस्थाओं जैसे सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, वाणिज्यिक बैंको के माध्यम से कृषि क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करता है। तालिका मे इस ऋण सहायता को वर्ष 2011 से 2016 तक के आंकड़ो से प्रदर्शित किया गया है।

तालिका : 1

कृषि क्षेत्र को सहायता उल्लेख 2011 से 2016 तक की गणना (करोड़ रूपये में)

संस्थान	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016
व्यावसायिक बैंक	368615.9	432490.95	527505.9	604375.5	604667.5
स्हयोगी बैंक	87964.6	111202.5	119963.8	138468.8	153294.6
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	54449.6	63680.9	82652.4	102482.5	119260.9
कुल	511028.9	607374.5	730122.8	845328.9	8772236.6

(क) श्रोत : नाबार्ड वार्षिक रिपोट 2015–2016

वर्ष 2011–2012 के दौरान सहकारी बैंको के द्वारा 16.38 प्रति फीसदी और 18.31 प्रति फीसदी इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 10.48 प्रति फीसदी पर दिख रहे है अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंक प्रथम स्थान पर वित्त सहायता प्रदायगी मे दिख रहे है।

(ख) याजना आधारित ऋण वितरण :

कृषि ऋण प्रदायगी याजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा कुल संमंको के आधार पर गणणानुसार स्पस्ष्ट है कि 80 प्रति प्रतिशत के हिसाब से कुल कृषि ऋण सहायता दिख रही है। जिसका विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है:

तलिका : 2

योजनाएँ	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016
फसल ऋण	396157.8	473499.8	548434.8	635409.9	705432.8
टर्म ऋण	114870.9	133874.9	181687.8	209915.6	171779.8
कुल	511028.9	607734.5	730122.6	845327.8	877.223.5

(ग) श्रोतः नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2015–2016

इस तालिका से स्पष्ट है कि फसल ऋण बढ़ता दिखाई दे रहा है जो कि वर्ष 2011–2012 मे 396157.8 करोड़ रूपये है इसी प्रकार 2015–2016 मे यह 705432.8 करोड़ रूपये रहा है इसी प्रकार टर्म ऋण भी 2011–2012 मे 114870.9 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2015–2016 मे 171779.8 करोड़ रूपये रहा। इस प्रकार 19.48 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक उतार चढ़ाव के रूप से वर्ष अर्तराल मे दिख रहा है।

(घ) नाबार्ड द्वारा पुनवित्त सहायता :

नाबार्ड वाणिज्यिक बैंको, सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता (आरएफआईएस) के साथ ग्रामीण विकास कार्यो का समर्थन करता है।

(च) लघु अवधि पुनवित्त :

नाबार्ड पुनवित्त द्वारा लघु अवधित के ऋण प्रदान करता है जो की कृषि उत्पादन, विपणन आदि विभिन्न कार्यो से संबंधित है अल्पावधि पुनवित्त सहायता तालिका वर्ष 2011–2012 से 2015–2016 तक निम्न प्रकार से हैः

तालिका :3

(2011 – 2012 और 2015–2016 तक की वित्तीय संस्थानों को अल्पावधि पुनवित्त सहायता)

वर्ष	राशि	पिछले वर्ष की तुलना मे परिवर्तन का प्रतिशत
2011 – 2012	49012.5	–
2012 – 2013	66417.8	35.50.2
2013 – 2014	81203.5	22.25.7
2014 – 2015	90619.8	11.59.6
2015 – 2016	71722.8	20.84.5

(छ) श्रोत : नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट

नाबार्ड द्वारा प्रदर्शित रिपोर्ट के आधार पर यह देखा जा सकता है कि अल्पावधि ऋण प्रदायगी मे भी लगातार वृद्वि देखी जा सकती है। वर्ष 2011 से वर्ष 2014 के दौरान 90619.8 करोड़ रूपये रहा है वर्ष 2015–2016 मे इसमे कमी आई है इस प्रकार परिवर्तन का तुलनात्मक प्रतिशत 35.51 प्रतिशत रहा जो कि घटते रूप मे 11.60 प्रतिशत दर्शाया गया है।

सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सहायताः गरीब ग्रामीण उत्थान को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकारो द्वारा गरीब परिवारो को अजीविका के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य बनाया गया है। जिसके अंतर्गत सेल्फ हैल्प ग्रुप (एसएचजी) बनाए गए है। इसका विवरण निम्न दर्शायी गई तालिका से स्पष्ट है।

तालिका : 4

वर्ष	राशि	स्वयं सहायता समूहों की संख्या (लाख में)	परिवर्तन प्रतिशत
2011 – 2012	14546.7	1196999.9	–
2012 – 2013	16533.5	1147998.9	12.66
2013 – 2014	20584.6	1219820.9	24.59
2014 – 2015	24016.5	1366420.6	16.69
2015 – 2016	34067.8	823579.7	41.86

(ज) श्रोतः नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2015–2016

उपरोक्त तालिका के अनुसार एसएचजी को सूक्ष्म वित्त सहायता की राशि मे वर्ष 2011–2012 मे 14546.7 की अपेक्षा 2016–2016 मे 34.067.8 बढ़ी है। परंतु यदि यह स्वयं सहायता समूहों को देखे तो उसमे 2011–2012 से 2015–2016 मे वर्ष दर वर्ष परिवर्तन दिख रहा है।

V निष्कर्ष

यदि हम पूर्व प्रथा पर ध्यान दे तो साहूकारी व्यवस्था का अंत होता दिख रहा है क्योंकि नाबार्ड की स्थापना ने गरीबो के शोषण का अंत करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1904 के बाद वित्त पोषण एजेंसियां वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए। वाणिज्यिक बैंको ने उस समय वित्त प्रदायगी से अपने आप को अलग किया साथ ही रिज़र्व बैंक की असमर्थता भी ग्रामीण विकास वित्त सहायता मे देखी गई । 1982 में नाबार्ड की स्थापना कर इस कमी को पूरा किया गया नाबार्ड द्वारा पुनवित्त सहायता प्रदान की गई जिससे कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का विकास संभव होता दिख रहा है साथ ही वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक ने भी नाबार्ड पुनवित्त गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका निभाई है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार योजना नीतियों में भी सामंजस्य स्थापित कर नाबार्ड की भूमिका कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदायगी मे दिख रही है। नाबार्ड प्रयासों के द्वारा कृषि उपज, छोटे पैमाने पर उद्योग, कुटीर और गांव उद्योगों, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प आदि विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा मिल सका है जो कि प्रतिवर्ष नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट से स्पस्ट हो रहा हैं। नाबार्ड पुनवित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं में एक शीर्ष वित्तीय एजेंसी के रूप मे कार्य करता है। इसके साथ ही पुनवित्त सुविधा के लिए राज्य कॉआपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि वित्तपोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने दायित्व को निभा रहे है। नाबार्ड ने एक एकीकृत संगठन के रूप में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई गतिविधियां शुरू की है। विभिन्न संस्थानों को कृषि सहायता प्रदान करने मे यदि

देखा जाए तो वाणिज्यिक बैंक प्रथम स्थान पर दिख रहे है। इसी प्रकार सहकारी बैक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैक भी अपनी अच्छी स्थिति के साथ वित्त पोषण मे प्रमुख भूमिका निभा रहे है। इन बैंको के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को भी वित्त के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है जिसकी गणना से देखा जाए तो वर्ष 2011–2012 से 2015–2016 तक के समंको मे वित्तपोषण मे वृद्वि दिख रही है।

संदर्भ

[1] Dr.M.Kumudini, 26THE ROLE OF NABARD IN THE RURAL DEVELOPMENT,Volume-6, Issue-1, January - 2017 • ISSN No 2277 – 816, r 2014 • ISSN No 2277 - 8179 Volume-6, Issue-1, January - 2017 • ISSN No 2277 - 8160 IF : 3.62 | IC Value 80.

[2] Dr.D.M.Mithani&Prof.E.Gordon, Financial Services, Banking and Insurance, Himalaya Publishing House, Hyderabad, 2015. 2. Dr.A.V.Ranganadhachary, Dr.RudraSai Baba and Dr.K.Anjaneyulu, Financial Services, Banking and Insurance, Kalyani Publishers, New Delhi, 2014. 3. www.nabard.com 4. www. role of NABARD in development of rural India 5. Annual Report of NABARD 2015-16

[3] https://hindi.bankersadda.com/2020/08/nabard-full-form-2020-what-does-nabard-stand-for-in-hindi.html

[4] Nabard Report official website: www.nabard.org